

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कांग्रेस का देशभर में प्रदर्शन

दिल्ली-पटना में मार्च,देहरादून में कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़े,काँकरोच पार्टी बोली...2 अक्टूबर से आंदोलन करेंगे

नई दिल्ली,25 सितम्बर 2026। कांग्रेस शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में प्रदर्शन कर रही है। उत्तराखंड के देहरादून में कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। पटना में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इधर,काँकरोच जनता पार्टी ने शुक्रवार को कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया तो 2 अक्टूबर से देशव्यापी आंदोलन करेंगे। काँकरोच जनता पार्टी ने गुरुवार को ज्ञानेश कुमार को 48 घंटे की डेडलाइन दी थी। एसआईआर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में एसआईआर के फैसलों,दिशा-निर्देशों और सॉफ्टवेयर बदलावों को असंवैधानिक घोषित करने और करीब 13 करोड़ वोटर्स के नाम हटाने की एसआईटी जांच की मांग है। दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, लखनऊ,कोलकाता और देहरादून समेत कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली में भी चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई और कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भी कांग्रेस विधायकों ने मुख्य चुनाव आयुक्त

को खिलाफ नारेबाजी की। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट, इरफान हाफिज लोन और इफ्तिखार अहमद ने प्रदर्शन किया। उन्होंने 'वोट बचाओ, लोकतंत्र बचाओ' और 'निष्पक्ष चुनाव के बिना लोकतंत्र नहीं' जैसे नारे लिखे बैनर दिखाए। लखनऊ में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन लखनऊ में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर में भारी बारिश हो रही थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कांग्रेस ने देशभर में राज्य चुनाव आयोग के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन का आह्वान किया है। पार्टी का कहना है कि वह एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध कर रही है। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने मुख्य चुनाव आयुक्त



बॉम्बे हाईकोर्ट में एसआईआर के खिलाफ 2 याचिकाएं

महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (एसआईआर) के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें एसआईआर की संवैधानिक वैधता, प्रक्रिया और लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि 2 चुनाव आयुक्तों की आपत्ति के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर से जुड़े 14 आदेश जारी किए। इन आदेशों को रद्द करने और दर्ज आपत्तियों को सार्वजनिक करने की मांग की गई है।

देशभर में कहा-कहा हुए प्रदर्शन?

- चंडीगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की।
- उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई।
- असम में गौरव गोर्गोई के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान गौरव गोर्गोई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।
- पंजाब में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वरिष्ठ ने ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ता 25 सितंबर को चंडीगढ़ में सेक्टर-17 स्थित चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च निकालेंगे।
- हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों को लेकर राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय के तहल तगे आधिकारिक बोर्ड पर कालिख पोत दी।
- अरुणाचल प्रदेश में विपक्षी कांग्रेस ने शुक्रवार को पार्टी के देशव्यापी आंदोलन के तहत इंदरनगर में प्रदर्शन किया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। प्रदेश कांग्रेस ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया रोकने, मतदाता सूची से जुड़े फैसलों की रवतंत्र जांच कराने और जांच पूरी होने तक आगामी चुनावों को स्थगित रखने की मांग की।

पवन खेड़ा ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की...

कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने शुक्रवार को एसआईआर के दौरान 'वीआईपी' मतदाताओं के लिए अलग व्यवस्था बनाए जाने का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाए और उनके इस्तीफे की मांग की। उन्होंने दावा किया कि देशभर में एसआईआर के जरिए 13 करोड़ से अधिक लोगों को मताधिकार से वंचित किया गया है और दिल्ली में चुनाव आयोग ने आम मतदाताओं तथा 'वीआईपी' मतदाताओं के लिए अलग-अलग व्यवस्था बनाई है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में खेड़ा ने कहा कि एक वेबसाइट की रिपोर्ट में एसआईआर से जुड़े अधिकारियों को 'वीआईपी' मतदाताओं की पहचान करने के निर्देश दिए जाने और एक अखबार की रिपोर्ट में बीएलओ ऐप में 'मार्क वीआईपी' सुविधा जोड़े जाने की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि बीएलओ ऐप में यह सुविधा 30 जुलाई को

जोड़ी गई थी और इसके जरिए बृथ लेवल अधिकारी सत्यापन के दौरान किसी मतदाता को 'वीआईपी' के रूप में चिह्नित कर सकते हैं। इसके बाद प्रविष्टि की जांच पड़ोसियों, ईआरओ और दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के स्तर पर की जाती है। चुनाव आयोग के मार्च 2023 के मैन्युअल में सांसदों, विधायकों, घोषित पदों पर बैठे लोगों तथा कला,संस्कृति,पत्रकारिता, खेल,न्यायपालिका और लोक सेवाओं से जुड़े कुछ लोगों को 'मार्कड इलेक्टर्स' के रूप में चिह्नित करने का प्रावधान बताया गया है। खेड़ा ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ने अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को नजरअंदाज किया और चुनाव आयोग को अकेले संचालित किया। उन्होंने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त को अपनी जिम्मेदारी से हट जाना चाहिए।



जंतर-मंतर पर वाम दलों का प्रदर्शन,दीपांकर समेत हिरासत में...

दिल्ली के जंतर-मंतर पर वाम दलों,छात्र संगठनों और सिविल सोसायटी के जुड़े लोगों ने भी प्रदर्शन किया। इसमें CPI(M) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य,योगेंद्र यादव,AISA की अध्यक्ष नेहा,वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण,पारदर्शिता कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और योगेंद्र यादव समेत कई लोग शामिल हुए।



उत्तर प्रदेश में बनी ब्रह्मोस पाकिस्तान की उड़ा रही है नींद : अमित शाह

नोएडा,25 सितम्बर 2026। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना है। निवेश का माहौल की पहली प्राथमिकता है कि कानून व्यवस्था ठीक हो। अनुकूल औद्योगिक नीति बने। उद्योग को बढ़ावा और सुविधा दिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह ने इंडिया एक्सपोजे सेंटर एंड मार्ट में पांच दिवसीय उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। यहां उद्योग के लिए अच्छा वातावरण है। उन्होंने कहा कि एक जमाने में यूपी में माफियाओं का शासन चलता था। वर्ष 2017 में भाजपा की सरकार यहां पर बनी। उसके बाद यूपी से माफियाओं को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल बना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन बार प्रधानमंत्री बनकर नीतियों का



निर्माण किया तथा नीतियों को जमीनी स्तर पर सही तरह से पहुंचाया। उन्होंने कहा कि अनुभव के आधार पर नीतियों में जो बदलाव करने थे और जो नई नीतियां बनानी थी उसमें भी प्रधानमंत्री ने स्फूर्ति दिखाकर बनाया और भारत को पूरे विश्व में एक आकर्षक उत्पादन का हब बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कुछ वक्रदृष्ट लोग भारत की जीडीपी के आंकड़ों को भी झुठलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने जीडीपी के 7.8 ग्रोथ को प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में इतनी अशांति के माहौल के बीच में भी भारत ने सबसे ज्यादा विकास ग्रोथ प्राप्त किया है। अपनी विकास दर को बनाए रखा है और उसे

यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में बढ़ रहा निवेश

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़ और कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर के छह नोड विकसित किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए निवेश आ रहा है। देश का रक्षा उत्पादन अब करीब 1.78 लाख करोड़ रुपये को पार कर चुका है और 2013-14 की तुलना में रक्षा उत्पादों के निर्यात में 56 गुना वृद्धि हुई है। आज भारत के रक्षा उत्पाद करीब 80 देशों को निर्यात किए जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर और अनुकूल नीतियों के जरिए निवेश को सुगम बनाने का काम किया है। अमेठी में निर्मित एफ-203 राफेल और उत्तर प्रदेश में बन रहे रक्षा उत्पाद देश की नई औद्योगिक क्षमता को दर्शाते हैं।

आगे भी बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि साल 2047 तक का विश्व में हर क्षेत्र में भारत के नंबर वन बनने का संकल्प पूरा होगा।

दिल्ली हाईकोर्ट का मेटा को आदेश...पीएम मोदी के साथ महिला की मॉर्फेड फोटो हटाएं,दीपके सहित चार को मिला नोटिस

नई दिल्ली,25 सितम्बर 2026। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की गई छीपफेक और मॉर्फेड तस्वीरों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने मेटा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला की कथित तौर पर मॉर्फेड तस्वीर दिखाई गई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस गिरीश कठपालिया की पीठ ने की। महिला ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उसकी तस्वीर का इस्तेमाल एआई फेस-स्वैपिंग टूल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीर तैयार करने के लिए किया गया और फिर उसे सोशल मीडिया पर फैलाया गया। यह पूरा मामला एक महिला की कथित मॉर्फेड और छीपफेक तस्वीर से जुड़ा है। याचिका के अनुसार, जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला की निजी तस्वीर का कथित तौर पर बिना अनुमति इस्तेमाल किया गया और एआई फेस-स्वैपिंग टूल की मदद से उसके चेहरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक आपत्तिजनक तस्वीर पर मॉर्फ कर दिया गया। महिला ने आरोप लगाया कि इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर फैलाया गया और उसे जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। मामले में एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मेटा को संबंधित आपत्तिजनक कंटेंट को उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले की



संवेदनशीलता पर भी टिप्पणी की। रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा कि यह मामला केवल एक महिला से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसमें देश के प्रधानमंत्री भी शामिल हैं।

सीजेपी नेताओं को भी नोटिस

इसके साथ ही मामले में कोर्ट ने काँकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) से जुड़े नेताओं सीरव दास, अभिजीत दिपके,अशुतोष रंका और रत्ना सिंह को भी नोटिस जारी किया है। महिला ने अपनी याचिका में इन लोगों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ उसकी मॉर्फेड और अश्लील तस्वीर को फैलाया है। हालांकि,ये आरोप याचिका में किए गए दावे हैं और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। याचिका ने आरोप लगाया है कि नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर महिला की निजी तस्वीर का बिना अनुमति इस्तेमाल किया गया है।

मिलन प्रधान को हाईकोर्ट से झटका

गिरफ्तारी से राहत वाला आदेश खारिज डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का आदेश पलटा कोलकाता,25 सितम्बर 2026। कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच (खंडपीठ) ने शुक्रवार को कांग्रेस के नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी मिलन प्रधान को 2007 के एक आपराधिक मामले में मिली राहत खत्म कर दी। मुख्य न्यायाधीश रवींद्र विठ्ठलराव घुगे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिंगल बेंच (एकल पीठ) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पुलिस को 12 अक्टूबर तक प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया था। पीठ में न्यायमूर्ति ओम नारायण राय भी शामिल थे। अदालत ने कहा कि आपराधिक कानून में किसी आरोपी को इस तरह की अंतरिम सुरक्षा देने का कोई प्रावधान नहीं है। पीठ ने कहा कि अगर किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो वह जमानत मांग सकता है। वहीं, गिरफ्तारी की आशंका होने पर आरोपी अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख कर सकता है। डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि कानून सभी के लिए समान है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के मामले में अलग तरीके से विचार नहीं किया जा सकता। सिंगल बेंच का आदेश रद्द होने के बाद कांथी एसीजेएम अदालत की ओर से प्रधान को 7 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश प्रभावी रहेगा।



पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना सरकार का विजन : नितिन गडकरी



भोपाल,25 सितम्बर 2026। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना सरकार का विजन है। देश में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सुधारने के लिए 5 एजेंडा तैयार किए गए हैं, जिसमें पहला क्लीन ट्रांसपोर्ट है। उन्होंने कहा कि देश के एयर पॉल्यूशन में करीब 40 प्रतिशत हिस्सेदारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर की है, जिसकी जिम्मेदारी वे लेते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रदूषण की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की है और प्रदूषण कम करना सरकार का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री गडकरी शुक्रवार को मध्य प्रदेश में 21 साल बाद लोक परिवहन व्यवस्था के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। राजधानी भोपाल के भेल दशरथा मैदान से प्रदेश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 7 शहरों के लिए 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि गरीबों को एसी बस में अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। डीजल बसों की तुलना में टिकट कारिया 30 प्रतिशत कम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह उनका सपना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पहले साल प्रदेश में 1,500 बसें चलाने का लक्ष्य है। बस सेवा के विस्तार के जरिए शहरों के साथ गांवों को भी जोड़ा जाएगा और 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों तक बस कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने आगे चलकर 2031 तक 15 हजार बसों के संचालन का लक्ष्य भी तय किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बन चुकी हैं। इससे छोटे गांवों और कस्बों से आवागमन आसान हुआ है और स्कूल-कॉलेज तथा शहरों तक पहुंच की सुगम हुई है।

सरकार ने मणिपुर,नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में AFSPA की समयसीमा बढ़ाई, 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए लागू...

नई दिल्ली,25 सितम्बर 2026। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के तीन राज्यों मणिपुर,नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल अधिनियम यानी अफसपा को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी गजट अधिसूचनाओं के मुताबिक, इन इलाकों में अफसपा 1 अक्टूबर 2026 से अगले छह महीने तक लागू रहेगा। हालांकि, सरकार इसे इससे पहले वापस ले सकती है। यह फैसला तीनों राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है। अधिसूचनाओं में अफसपा की धारा 3 के तहत संबंधित क्षेत्रों को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है। मणिपुर में गृह मंत्रालय ने पूरे राज्य को 'अशांत क्षेत्र'



घोषित किया है, लेकिन पांच जिलों के 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इफाल पश्चिम जिले में इंपफल, लाफिल, सिटी, सिंगजामेई, पटसोई और वांगोई थाना क्षेत्र को बाहर रखा गया है। वहीं, इफाल पूर्व में पोरोमपत, हेडगांग और इरिलबुंग थाना क्षेत्र शामिल नहीं हैं। इसके अलावा थौबल जिले में

थौबल थाना, बिष्णुपुर जिले में बिष्णुपुर और नंबोल थाना तथा काकचिंग जिले में काकचिंग थाना क्षेत्र को भी अफसपा की अधिसूचना से बाहर रखा गया है। नगालैंड में अफसपा को नौ जिलों में अगले छह महीने के लिए बढ़ाया गया है। इनमें दीमापुर, निजलैंड, चुमोकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक, परेन और मेल्तुरी शामिल हैं। इन जिलों को अफसपा की धारा 3 के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है। इसके अलावा कोहिमा,मोकोकचुंग,लोचेंलेंग,वोखा और जुन्हेबोटो जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों को भी अधिसूचना में शामिल किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तिरप,चांगलांग और लोंगलेंडा जिलों में अफसपा की अवधि बढ़ाई गई है।

सेवा यात्रा के अनुभव जीवन की पूंजी,भारत को किताबों से नहीं गांव-गांव जाकर समझें : पीएम मोदी

नई दिल्ली,25 सितम्बर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 'सेवा संकल्प अभियान' के सेवा यात्रियों से कहा कि यात्रा के दौरान अलग-अलग राज्यों के गांवों में लोगों से जुड़ने और सेवा कार्य करने के अनुभव उनके जीवन का अमूल्य पूंजी बनेंगे। उन्होंने युवाओं से कहा कि भारत की विविधता, गांवों की संस्कृति और समाज की सेवा भावना को किताबों से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता, इसके लिए गांव-गांव जाकर लोगों के बीच रहना जरूरी है। मोदी ने यात्रियों से यात्रा के अनुभवों को लिखने और दर्ज करते रहने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने 'सेवा संकल्प



अभियान' के तहत वजनार से वाराणसी जाने वाले दल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद में कहा कि पिछले करीब 10-12 वर्षों में गांवों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में बड़ा बदलाव आया



है तथा शहर और गांव के बीच का अंतर काफी कम हुआ है। उन्होंने नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए यात्रियों से पूछा कि क्या उन्हें गांवों में बदलाव महसूस हो रहा है और क्या

ग्रामीण भी इस बदलाव की चर्चा करते हैं। यात्रा युवाओं को इन बदलावों को प्रत्यक्ष रूप से देखने और लोगों से सीधे संवाद करने का अवसर दे रही है। मोदी ने सेवा यात्रियों को सुरक्षा का भी ध्यान रखने की सलाह दी। संवाद के दौरान यात्रियों के भगवा साफे का उल्लेख करते हुए उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, 'बाइक चलाते समय आप यह साफा पहनकर तो नहीं चलते होंगे? हेलमेट पहनते होंगे ना? साफा की हेलमेट मत समझ लेना।' उन्होंने यात्रियों से परिवार के संपर्क में रहने, जिन क्षेत्रों से गुजरें वहां के लोगों से जुड़ने और उनके संपर्क नंबर लेने तथा वाट्सएप समूह बनाने का भी

सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें याद याद किया। दीनदयाल उपाध्याय के समाज जीवन में कर्तव्यों से जुड़े सात सूत्रों- सेवा भाव,संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता,संवेदना और संवाद का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यही सेवा संकल्प यात्रा की आत्मा है। गांवों में बच्चों को पढ़ाई की समझी देना,पौधारोपण करना, वृद्धजनों की सेवा करना,महिलाओं से संपर्क करना और युवाओं के सपनों को समझना अलग-अलग कार्य दिखाई देते हैं, लेकिन इनके पीछे मानवता को केंद्र में रखकर समाज की सेवा का भाव समान है।



मुसलाधार बारिश और अचानक बाढ़ का गंभीर खतरा बना हुआ है। चक्रवात और मानसून तंत्र के कारण देश के 9 राज्य सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। चक्रवात के असर से ओडिशा के दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है।

सिक्किम में बढ़ा भूस्खलन : 20 से अधिक मकान बहे अर्नब चक्रवात के असर से ओडिशा में बाढ़ का खतरा

नई दिल्ली,25 सितम्बर 2026। चक्रवाती तूफान 'अर्नब' और उत्तर-पूर्वी भारत में जारी मुसलाधार बारिश ने देश के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। सिक्किम के ग्यालशिग जिले के रिबी गांव में गुरुवार रात हुए भीषण भूस्खलन में 20 से अधिक निहयशी मकान और सरकारी क्वार्टर बह गए। गनीमत यह रही कि समय रहते सतर्कता बरतने के कारण अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है। दूसरी ओर, बंगाल की खाड़ी से उठा 'अर्नब' चक्रवात भले ही कमजोर पड़ चुका हो, लेकिन इसके प्रभाव से ओडिशा और आसपास के राज्यों में



40 लाख का सौदा, फर्जी दस्तावेज और आदिवासी जमीन... अब कर्मचारियों-अधिकारियों की भूमिका पर भी उठा सवाल

जमीन के खरीदार तक पहुंची पुलिस... अब 'फर्जी कागज' बनाने वालों की बारी?

शिकायत से एफआईआर, एफआईआर से गिरफ्तारी... अब सरकारों तंत्र की भूमिका की जांच क्या?

आलोक दुबे की शिकायत के बाद खुलती गई घटना, आजाद गिरफ्तार... फर्जी दस्तावेजों का 'जनक' कौन?

आदिवासी जमीन का सौदा, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र से वंशावली तक, किसने तैयार किया पूरा दस्तावेजों तस्तर?

आजाद इराकी गिरफ्तार, लेकिन बड़ा सवाल बाकी—फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र किसने बनाया, वंशावली किसने तैयार की?

कलेक्टर की जांच से खुला जमीन फर्जीवाड़ा, पहली गिरफ्तारी के बाद अब 'कागज बनाने वालों' की तलाश जरूरी

एक जैलाल की वंशावली, दूसरे जैलाल की जमीन! अब पुलिस खोलेगी फर्जी दस्तावेजों की अटली कड़ी

प्रतीक्षा बस स्टैंड जमीन मामले: खरीदार गिरफ्तार, पर मृत्यु प्रमाण-पत्र से नामांतरण तक किसने बिछाया तस्तर?

—संवाददाता—
अंबिकापुर, 25 सितम्बर 2026
(घटती-घटना-2)

प्रतीक्षा बस स्टैंड के पास स्थित बेशकीमती जमीन के कथित फर्जी अंतरण का मामला अब एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है, शिकायत, प्रशासनिक जांच और कलेक्टर के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई और अब पुलिस ने इस मामले में पहली गिरफ्तारी की कार्रवाई की है, 25 सितंबर को सरगुजा पुलिस की जारी प्रेस विज्ञापन के अनुसार, थाना मणिपुर, साइबर सेल और रायपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने आजाद इराकी को रायपुर से गिरफ्तार किया है, पुलिस के अनुसार विवादित जमीन के सौदे की रकम 40 लाख रुपये बताई गई है और आरोपी ने पुलिस के समक्ष दिए गए मेमोरेण्डम कथन में दस्तावेजों के फर्जी होने की जारी प्रेस विज्ञापन के बावजूद जमीन का सौदा करने की बात स्वीकार की है।

लेकिन गिरफ्तारी के साथ मामला खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब जांच का दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल सामने खड़ा हो गया है जिस फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र और कथित गलत वंशावली के आधार पर पूरी जमीन की दस्तावेजी कहानी आगे बढ़ी, उसे तैयार किसने किया? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में किसी शासकीय कर्मचारी या अधिकारी की भूमिका थी? यदि थी तो वह भूमिका किस स्तर तक थी दस्तावेज तैयार करने, सत्यापन करने, वारिसान दर्ज करने, फौती नामांतरण करने या राजस्व रिकॉर्ड बदलने तक? प्रशासनिक जांच में पटवारी तथा ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच-सचिव की भूमिका को लेकर सवाल सामने आए हैं।

2 सितंबर की शिकायत से खुला मामला, कलेक्टर ने कराई जांच—मामले की शुरुआत 2 सितंबर 2026 को हुई शिकायत से हुई, भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने कलेक्टर सरगुजा के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर पुराने राजस्व रिकॉर्ड और जमीन के दस्तावेजों के आधार पर सवाल उठाए थे, उनका मुख्य सवाल था कि यदि जमीन पुराने सेटलमेंट और अधिकार अभिलेख में आदिवासी खातेदार के नाम दर्ज थी, तो बाद में उसके वारिस और स्वामित्व की स्थिति कैसे बदल गई, शिकायत में प्रतीक्षा बस स्टैंड के पास स्थित भूमि के जल क्षेत्र को मिट्टी डालकर पाटने और वहां प्लांटिंग किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया था, प्रशासन

खसरा नंबर 3714: तालाब भी, आदिवासी भूमि का पुराना रिकॉर्ड भी

मामला खसरा नंबर 3714 से जुड़ा है, उपलब्ध दस्तावेजों में इसका रकबा 0.250 हेक्टेयर/0.231 हेक्टेयर बताया गया है, पुलिस की प्रेस विज्ञापन में इसे नगर निगम के मास्टर प्लान-2021 और तालाबों की शासकीय सूची में दर्ज 6.25 एकड़ तालाब क्षेत्र का हिस्सा बताया गया है, जांच से जुड़े दस्तावेजों और रिपोर्टों के अनुसार यह क्षेत्र स्थानीय लोगों के निस्तारी, स्नान और छठ पूजा जैसे सामाजिक-धार्मिक उपयोग से जुड़ा रहा है, प्रकाशित जांच विवरण में इसे रिंगबोंध तालाब क्षेत्र से भी जोड़ा गया है, यही वजह है कि विवाद केवल जमीन की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं है, एक तरफ जमीन के पुराने स्वामित्व और जाति संबंधी रिकॉर्ड का सवाल है, तो दूसरी तरफ उसके तालाब क्षेत्र के रूप में दर्ज होने का भी प्रश्न है।

1954-55 से पहले के रिकॉर्ड में जैलाल पिता बोधन गोंड

प्रशासनिक जांच के अनुसार खसरा नंबर 3714 की भूमि 1954-55 से पहले के राजस्व अभिलेख में जैलाल पिता बोधन, जाति गोंड, अनुसूचित जनजाति के नाम दर्ज थी, यही रिकॉर्ड अब पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है, क्योंकि यदि पुराना अधिकार अभिलेख किसी अनुसूचित जनजाति खातेदार के नाम था, तो बाद के वर्षों में भूमि का वारिस कौन बना, किस आधार पर बना और फिर भूमि गैर-अनुसूचित जनजाति के नाम कैसे पहुंची—इन सभी सवालों का जवाब दस्तावेजों की पूरी श्रृंखला से ही मिलेगा, पुलिस की प्रेस विज्ञापन में भी कहा गया है कि आरोपियों ने कथित रूप से फर्जी मृत्यु प्रमाण-पत्र और कूटरचित दस्तावेजों का सहारा लेकर दूसरे व्यक्ति की वंशावली और नामांतरण का दुरुपयोग किया।

ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अंबिकापुर एसडीएम से जांच कराई, एसडीएम की जांच के बाद कलेक्टर के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसके आधार पर 23 सितंबर 2026 को कलेक्टर कार्यालय ने संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए, साथ ही भूमि को विधिवत शासन में निहित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए, यानी यह मामला सीधे पुलिस कार्रवाई तक नहीं पहुंचा, इसके पीछे शिकायत से लेकर प्रशासनिक जांच तक की पूरी प्रक्रिया हुई।

फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र: पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी—प्रशासनिक जांच में मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर गंभीर विवेक सामने आई, जांच में जैलाल पिता बोधन की मृत्यु 23 अप्रैल 1976 से संबंधित मृत्यु प्रमाण पत्र का उल्लेख हुआ। लेकिन नगर निगम अंबिकापुर से कराए गए सत्यापन में यह सामने आया कि उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था और निगम द्वारा जारी नहीं किया गया था, यह जानकारी 4 मई 2026 के निर्णायक जवाब से जुड़ी बताई गई है, यही से मामला एक सामान्य राजस्व विवाद से आगे बढ़ता है, अगर मृत्यु प्रमाण पत्र निगम ने जारी ही नहीं किया तो वह बना कहाँ से? किसने बनाया? किसके आवेदन पर बनाया? किसने उसमें दर्ज तथ्यों का सत्यापन किया? किस दस्तावेज के आधार पर उसे राजस्व प्रक्रिया में प्रस्तुत किया गया? और सबसे महत्वपूर्ण—क्या किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी ने उस दस्तावेज को सही मानते हुए आगे की कार्रवाई की? इन सवालों का जवाब अभी सामने आना बाकी है।

एक जैलाल की वंशावली, दूसरे जैलाल की जमीन—यहीं उपड़ी पूरी कहानी—मामले की जांच में सबसे महत्वपूर्ण विवेक वारिसान संबंधी दस्तावेजों को लेकर सामने आई है, प्रशासनिक जांच से जुड़े विवरण के अनुसार ग्राम अमलभिन्नी के पटवारी ने जैलाल पिता देवराम के वारिसों की जानकारी तैयार की थी, आरोप/जांच का महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसी जानकारी का इस्तेमाल कथित तौर पर जैलाल पिता बोधन की भूमि के फौती नामांतरण के लिए किया गया, अब यही सवाल पुलिस की जांच का केंद्रीय बिंदु होना चाहिए, जैलाल पिता देवराम और जैलाल पिता बोधन की पहचान कैसे निर्धारित हुई? क्या दोनों अलग-अलग व्यक्ति थे? यदि अलग थे तो एक की वंशावली दूसरे की भूमि के नामांतरण में कैसे इस्तेमाल हुई? उस वंशावली को किसने तैयार किया? किसने उसे प्रमाणित किया? और राजस्व रिकॉर्ड में उसे स्वीकार किस स्तर पर किया गया? प्रशासनिक जांच में यही विवेक वारिसान पूरे मामले को गंभीर बनाती है।

पटवारी से लेकर पंचायत तक—अब सरकारी तंत्र की भूमिका भी जांच का विषय—यही वह बिंदु है जहां इस मामले का दूसरा बड़ा सवाल सामने आता है, प्रशासनिक जांच के विवरण के अनुसार पटवारी द्वारा तैयार की गई वारिसान जानकारी का उल्लेख जांच में है, साथ ही ग्राम पंचायत अमलभिन्नी के तत्कालीन सरपंच और सचिव की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं, यह ध्यान रखना जरूरी है कि जांच में किसी कर्मचारी या अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाना और उसका आपराधिक रूप से दोषी होना दो अलग बातें हैं, लेकिन पुलिस के लिए अब यह जांचना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कराने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई? पंचायत स्तर पर कौन-कौन से दस्तावेज बने? वारिसान/वंशावली किसने तैयार की? उसे किसने प्रमाणित किया? पटवारी ने किस आधार पर वारिसों की जानकारी तैयार की? फौती नामांतरण के दौरान पुराने अधिकार अभिलेख की जांच हुई या नहीं? नामांतरण किस अधिकारी के आदेश से हुआ? रजिस्ट्री से पहले राजस्व रिकॉर्ड और प्रस्तुत दस्तावेजों का मिलान किस स्तर पर किया गया? यही जांच तय करेगी कि यह केवल निजी पक्षों के बीच कथित दस्तावेजी फर्जीवाड़ा था या सरकारी रिकॉर्ड तक पहुंचने वाली प्रक्रिया में भी किसी स्तर पर मदद मिली।

कलेक्टर के आदेश के बाद एफआईआर, अब पुलिस जांच में बदला मामला—कलेक्टर की जांच के बाद 23 सितंबर को एफआईआर के निर्देश दिए गए, इसके बाद उपलब्ध एफआईआर दस्तावेज के अनुसार 24 सितंबर 2026 को थाना मणिपुर में अपराध क्रमांक 168/2026 दर्ज हुआ, मामले में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 318(4), 338, 336(3), 340(2) एवं 61(2) लगाई गई हैं, इससे यह स्पष्ट है कि मामला अब राजस्व विभाग की फाइल तक सीमित नहीं रहा, पुलिस ने इसे आपराधिक विवेचना में ले लिया है।

25 सितंबर को पुलिस की कार्रवाई—रायपुर से आजाद इराकी गिरफ्तार— 25 सितंबर की सरगुजा पुलिस प्रेस विज्ञापन के अनुसार डीआईजी एवं एसएसपी के निर्देशन में थाना मणिपुर, साइबर सेल और रायपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी आजाद इराकी को रायपुर से गिरफ्तार किया, पुलिस के अनुसार तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपी के संभावित ठिकाने की पहचान की गई और रायपुर पुलिस टीम के साथ कार्रवाई की गई, पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान, आजाद इराकी, पिता रियाजुद्दीन इराकी, उम्र 43 वर्ष, निवासी मस्जिद मोहल्ला जयनगर, थाना जयनगर, जिला सूरजपुर



के रूप में हुई है, पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने मेमोरेण्डम कथन में यह स्वीकार किया कि उसे जमीन के दस्तावेज फर्जी और कूटरचित होने की जानकारी थी, इसके बावजूद उसने 40 लाख रुपये में विवादित जमीन का सौदा किया, पुलिस ने पुराना साक्ष्य पाए जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की जानकारी दी है, किसी आरोपी का पुलिस पूछताछ में दिया गया कथन अंतिम न्यायिक निष्कर्ष नहीं होता, उसकी कानूनी स्थिति अदालत में साक्ष्यों के परीक्षण से तय होगी।

नौ लोगों के खिलाफ कार्रवाई, कई आरोपी अभी फरार—कलेक्टर की जांच के आधार पर क्रेता-विक्रेता समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, प्रकाशित प्रशासनिक विवरणों में चंद्रशेखर यादव, आजाद इराकी, नोहरसाय, रामकुमार, श्रीलाल, पूर्णिमा, जनक, चंद्रभान यादव और मीरा यादव के नाम सामने आए हैं, पुलिस की प्रेस विज्ञापन में बताया गया है कि मामले में शामिल अन्य आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है, इससे स्पष्ट है कि आजाद इराकी की गिरफ्तारी को पुलिस इस प्रकरण की अंतिम कार्रवाई नहीं मान रही है, जांच अभी जारी है और अन्य आरोपियों की भूमिका भी विवेचना के दायरे में है।

40 लाख का सौदा—लेकिन जमीन की असली कीमत और भी बड़ा सवाल—पुलिस की प्रेस विज्ञापन में विवादित जमीन का सौदा 40 लाख रुपये में किए जाने की बात सामने आई है, लेकिन प्रतीक्षा बस स्टैंड और रिंग रोड जैसे शहर के महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित जमीन की बाजार कीमत को लेकर अलग-अलग रिपोर्टों में इसे करोड़ों रुपये की बेशकीमती जमीन बताया गया है, इसलिए जांच का एक पहलु यह भी हो सकता है कि जमीन का वास्तविक बाजार मूल्य क्या था, सौदे की रकम किस माध्यम से दी गई और रकम का लेन-देन किन लोगों के बीच हुआ, हालांकि इस संबंध में उपलब्ध पुलिस प्रेस विज्ञापन 40 लाख रुपये के कथित सौदे का उल्लेख करती है, उससे आगे भुगतान के तरीके या धन के स्रोत के बारे में अभी कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

तालाब की जमीन को पाटकर प्लांटिंग की शिकायत ने बढ़ाई गंभीरता—मामला तब और गंभीर हुआ जब जमीन के जल क्षेत्र को मिट्टी डालकर पाटने और प्लांटिंग किए जाने की शिकायत सामने आई, मीडिया रिपोर्टों के

लेकर सवाल सामने आने के बाद इन बिंदुओं की पुलिस जांच और महत्वपूर्ण हो जाती है, यदि किसी शासकीय कर्मचारी या अधिकारी की भूमिका केवल लापरवाही तक सीमित थी तो उसकी प्रकृति अलग होगी, लेकिन यदि जांच में जानबूझकर गलत दस्तावेज तैयार करने, प्रमाणित करने, रिकॉर्ड बदलने या गलत नामांतरण में सहयायता करने के साक्ष्य मिलते हैं, तो मामला और गंभीर हो सकता है, अभी ऐसी किसी भूमिका को तथ्य के रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता। यह जांच का प्रश्न है और पुलिस को इसे दस्तावेजों के मूल स्रोत तक जाकर स्पष्ट करना होगा।

शिकायतकर्ता का सवाल अब पुलिस के सामने भी— आलोक दुबे की शिकायत से जिस मामले की प्रशासनिक जांच शुरू हुई, वह अब एफआईआर और गिरफ्तारी तक पहुंच चुका है, शिकायत में उठाया गया मूल सवाल था कि पुराने रिकॉर्ड में दर्ज जमीन की पहचान और वारिसों की स्थिति बाद के रिकॉर्ड में कैसे बदल गई, कलेक्टर की जांच ने दस्तावेजी विवेकगति को सामने रखा, कलेक्टर के आदेश के बाद एफआईआर हुई और अब पुलिस ने गिरफ्तारी की है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद शिकायत का दूसरा सवाल और बड़ा हो गया है—अगर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र था तो बनाने वाला कौन था? अगर वंशावली गलत थी तो तैयार किसने की? अगर वारिसान गलत था तो उसे प्रमाणित किसने किया? अगर नामांतरण गलत दस्तावेज पर हुआ तो राजस्व स्तर पर किसने उसे आगे बढ़ाया? इन सवालों का जवाब मिले बिना मामले की पूरी तस्वीर सामने नहीं आएगी।

शिकायत से गिरफ्तारी तक—पूरे मामले की टाइमलाइन

- 2 सितंबर 2026: भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने कलेक्टर से शिकायत की।
- इसके बाद: कलेक्टर ने एसडीएम अंबिकापुर से मामले की जांच कराई।
- जांच में: पुराने राजस्व रिकॉर्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान और फौती नामांतरण से जुड़ी विवेकगति का उल्लेख हुआ।
- 23 सितंबर 2026: कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए।
- 24 सितंबर 2026: थाना मणिपुर में अपराध क्रमांक 168/2026 दर्ज हुआ।
- 25 सितंबर 2026: सरगुजा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में आजाद इराकी को रायपुर से गिरफ्तार करने की जानकारी दी।
- अब: अन्य फरार आरोपियों की तलाश और दस्तावेजों की विवेक जांच जारी है।
- अब पुलिस के सामने सिर्फ जमीन नहीं, पूरा 'दस्तावेजी रास्ता' है—इस मामले की जांच की सबसे अहम कड़ी अब यही है पुराना अधिकार अभिलेख? मृत्यु प्रमाण पत्र? वंशावली/वारिसान? पंचायत स्तर के दस्तावेज? पटवारी की रिपोर्ट? फौती नामांतरण? राजस्व रिकॉर्ड? विक्रय दस्तावेज? रजिस्ट्री? जमीन का कब्जा/प्लांटिंग, इस पूरी श्रृंखला में जहां भी पहला गलत दस्तावेज तैयार हुआ, वहीं से कथित फर्जीवाड़े की असली शुरुआत मानी जा सकती है, आजाद इराकी की गिरफ्तारी ने पुलिस कार्रवाई की शुरुआत जरूर कर दी है, लेकिन मामले का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अभी बाकी है—फर्जी दस्तावेजों का स्रोत कौन था और सरकारी रिकॉर्ड तक उनकी पहुंच कैसे हुई? अगर जांच इस सवाल तक पहुंचती है और दस्तावेजों के आधार पर किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की भूमिका सामने आती है, तो कार्रवाई की दिशा जमीन के खरीदार-विक्रेता से आगे बढ़कर उस तंत्र तक जा सकती है जिसने कथित तौर पर दस्तावेजों को वैधता का रास्ता दिया, यही वह बिंदु है जहां प्रतीक्षा बस स्टैंड जमीन प्रकरण की असली परत खुल सकती है, सरगुजा पुलिस ने कहा है कि मामले की अधिम वैधानिक विवेचना जारी है और फरार सह-आरोपियों की तलाश की जा रही है।

गणेश विसर्जन जुलूस में बवाल : रास्ता देने की बात पर विवाद,दरिमा थाना प्रभारी से झूमाझटकी और वाहन में तोड़फोड़,छह गिरफ्तार...

डीजे और जुलूस से बाधित था मार्ग,समझाइश देने पहुंचे थाना प्रभारी से उलझे युवक...मणिपुर पुलिस ने छह आरोपियों को पकड़ा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

गणेश विसर्जन की आस्था और उत्सव के बीच मणिपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर में उस समय विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जब विसर्जन जुलूस के दौरान सड़क पर डीजे वाहन के साथ रास्ता बाधित होने को लेकर दरिमा थाना प्रभारी और जुलूस में शामिल लोगों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला कहासुनी से झूमाझटकी और वाहन में तोड़फोड़ तक पहुंच गया। पुलिस ने मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, दरिमा थाना प्रभारी शासकीय कार्य से अंबिकापुर की ओर आ रहे थे। ग्राम जगदीशपुर मेन रोड पर गणेश विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। जुलूस में पिकअप वाहन पर तेज आवाज में डीजे बज रहा था और इससे आम रास्ता बाधित हो गया था। थाना प्रभारी ने रास्ता देने तथा यातायात सुचारु करने के लिए जुलूस में शामिल लोगों को समझाइश देने का प्रयास किया। इसी दौरान कुछ लोग उनसे विवाद करने लगे। पुलिस का आरोप है कि विवाद बढ़ने के बाद आरोपियों ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की और थाना प्रभारी के साथ झूमाझटकी की। इतना ही नहीं, उनके वाहन के कांच तोड़कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना के बाद मामले की रिपोर्ट मणिपुर थाने में दर्ज कराई गई और पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू की।



मीडिया रिपोर्टों में मारपीट का भी उल्लेख

घटना के संबंध में सामने आई स्थानीय जानकारी ने बताया गया है कि दरिमा थाना प्रभारी एवं प्रशिक्षु डीएसपी निशांत कुरें रात में अपनी निजी कार से दरिमा से अंबिकापुर लौट रहे थे। कंटी-जगदीशपुर मार्ग पर गणेश विसर्जन जुलूस और डीजे के कारण यातायात प्रभावित था। रास्ता देने को लेकर विवाद बढ़ने के बाद उनके साथ हाथापाई तथा निजी वाहन में तोड़फोड़ किए जाने की बात रिपोर्ट की गई है। अंबिकापुर एसडीओपी राकेश बघेल के हवाले से भी कुछ रिपोर्टों में समझाइश के दौरान हमला होने की जानकारी दी गई है। हालांकि पुलिस की ओर से जारी विस्तृत प्रेस-नोट में मुख्य रूप से शासकीय कार्य में बाधा, झूमाझटकी और वाहन के कांच तोड़े जाने की घटना का उल्लेख किया गया है। इसलिए घटना के प्रत्येक पहलू का अंतिम स्वरूप विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा।

छह आरोपी गिरफ्तार : मामले की त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल छह गंभीरता को देखते हुए मणिपुर थाना पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया। पुछताछ में

डीजे और जुलूस की व्यवस्था पर भी उठे सवाल

घटना के बाद केवल आरोपियों की गिरफ्तारी से मामला खत्म नहीं होता। ऐसे आयोजनों में डीजे की आवाज, सड़क पर वाहनों की स्थिति,जुलूस की लंबाई,यातायात प्रबंधन और आपातकालीन आवागमन जैसे मुद्दों पर प्रशासन की जवाबदेही भी महत्वपूर्ण है। एक तरफ पुलिस धार्मिक आयोजनों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अपील करती है,दूसरी तरफ यदि मुख्य मार्ग पर जुलूस के कारण आवागमन पूरी तरह प्रभावित होता है और किसी वाहन को निकलने के लिए विवाद की स्थिति बनती है,तो यह व्यवस्था की कमी की ओर भी इशारा करता है।

लेकिन सार्वजनिक सड़क पर जुलूस निकालते समय यातायात और आम नागरिकों की आवाजही को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी है। इस घटना ने इसी बुनियादी सवाल को सामने ला दिया है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान डीजे, जुलूस और वाहनों की व्यवस्था के लिए पहले से पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? अगर पुलिस के अनुसार सड़क बाधित थी और थाना प्रभारी केवल रास्ता देने के लिए समझाइश दे रहे थे, तो बात इतनी जल्दी टकराव तक कैसे पहुंची- यह भी जांच का विषय है। दूसरी ओर, यदि किसी अधिकारी द्वारा समझाइश दिए जाने के बाद उसके साथ झूमाझटकी और वाहन में तोड़फोड़ की गई, तो यह भीड़ के कानून अपने हाथ में लेने की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। सबसे अहम सवाल यह भी है कि विसर्जन जुलूस जैसे संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले आयोजन में पुलिस की पर्याप्त मौजूदगी और यातायात नियंत्रण की व्यवस्था पहले से क्यों

नहीं थी। क्योंकि यदि रास्ता पहले से नियंत्रित होता, डीजे और जुलूस के लिए निर्धारित मार्ग स्पष्ट होता तथा पुलिस बल मौके पर मौजूद रहता, तो मामूली विवाद के हिंसक रूप लेने की संभावना कम की जा सकती थी। **पुलिस की कार्रवाई तेज, अब जांच की बारी** : घटना के बाद मणिपुर पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई जरूर तेज की है। लेकिन पुलिस के सामने अब यह भी चुनौती है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पत्ता से जांच की जाए-जुलूस में कितने लोग मौजूद थे,विवाद की शुरुआत किस बात से हुई, किसने झूमाझटकी की, वाहन में तोड़फोड़ किसने की और घटना में अन्य लोगों की क्या भूमिका थी। पुलिस ने अन्य संभावित सलिलस लोगों की भूमिका की भी जांच शुरू की है। उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों में भी छह लोगों की गिरफ्तारी के साथ अन्य लोगों की तलाश/भूमिका की जांच का उल्लेख किया गया है।

घुनघुट्टा बांध में डूबे 19 वर्षीय युवक का शव मिला,गेट के पास फंसा था

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

घुनघुट्टा बांध में गुरुवार की दोपहर छलांग लगाने वाले 19 वर्षीय युवक का शव शुक्रवार को करीब 1 बजे एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया। युवक का शव बांध के गेट के पास पानी में फंसा मिला। टीम ने काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मणिपुर थाना क्षेत्र निवासी रितिक गुरुवार दोपहर करीब 3 से 4 बजे स्कूटी से शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर घुनघुट्टा बांध पहुंचा था। बांध में इन दिनों पानी लबालब भरा हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक ने बांध के ऊंचाई वाले हिस्से से पानी में छलांग लगा दी। वहां मौजूद मछुआरों ने उसे डूबते देखा तो बचाने के लिए पानी में उतरे,लेकिन युवक गहरे पानी में चला गया और उनका पता नहीं चल सका। सूचना मिलने पर दरिमा पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की तलाश शुरू कराई गई। शाम होने के कारण रेस्क्यू अभियान रोकना पड़ा। शुक्रवार सुबह पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने दोबारा तलाश शुरू की। कई घंटे की मशक्कत के बाद टीम को युवक का शव बांध के गेट के पास फंसा मिला। युवक की मौत की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। युवक ने यह कदम क्यों उठाया, इसका कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि उसने घटना से एक दिन पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म 'आंशिकी-2' से संबंधित स्टैटस लगाया था। पुलिस उसके सोशल मीडिया अकाउंट और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। मौत के कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा।



आईटीआई भवन से विद्युतीकरण का सामान चोरी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।
लुंछा थाना क्षेत्र के ग्राम डडागांव में नवनिर्मित आईटीआई भवन से विद्युतीकरण का सामान चोरी होने का मामला सामने आया है। सहयक अभियंता विद्युत यांत्रिकी पीडब्ल्यूडी सभाग अंबिकापुर पुरजंन सिदार ने पुलिस को बताया है कि,ग्राम डडागांव में नवनिर्मित शासकीय आईटीआई भवन में एक साल पहले विद्युतीकरण का काम हुआ था। स्विच बोर्ड,कंप्यूटर बोर्ड,एससीबी,लाइटिंग कंडक्टर,सीलिंग फैन और परिसर में वरुणा कंपनी की समीक्षित पंप लगा था। 16 सितम्बर को आकस्मिक निरीक्षण में पाया गया कि सभी उपकरण खोलाकर चोरी कर लिए गए हैं। सिर्फ समरसिबल पंप की कीमत 16,800 रुपये है, बाकी सामान की कीमत का आंकलन जारी है। घटना की सूचना कार्यपालन अभियंता को दी गई है।

नकली जेवर को असली बताकर 5 महिलाओं से 2 लाख की ठगी

-संवाददाता-
रामानुजनगर,25 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।
सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना अंतर्गत नकली जेवर को असली बताकर ठगी करने का मामला सामने आया है। रामानुजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम शिवपुर की दुर्गावती सिंह समेत 5 महिलाओं के साथ 2 लाख 3 हजार 600 रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पीड़िता दुर्गावती सिंह पति रूपेश सिंह 30 वर्ष ने थाने में लिखित शिकायत देकर बताया कि मार्च-अप्रैल 2026 के बीच ग्राम नारायणपुर निवासी रूपेश साहू और उसका पिता ललन साहू गांव-गांव में घूमकर सोना-चांदी बेचने आए थे। दुर्गावती को इन्होंने सोने का बड़ा लॉकेट 2 नग, छोटा लॉकेट 1 नग,चांदी की पायल 1 नग और चांदी की अंगुठी 1 नग दिया और असली बताकर 80 हजार रुपये ले लिए। घर आने के बाद संदेह की स्थिति बनी और सोनार को दिखाया तो सभी जेवर नकली निकले। जांच में पता चला कि आरोपियों ने सिर्फ दुर्गावती ही नहीं, बल्कि उसी गांव की मालती पति भुवनेश्वर से 21 हजार, चमेली सिंह पति सुरेंद्र से 16 हजार, सांता सिंह पति नरेंद्र से 47,200 और कलावती सिंह पति देव सिंह से 39,400 रुपये की ठगी नकली जेवर धमाकर की है। सभी को इसी तरह नकली जेवर असली के रेट पर धमाए गए थे। पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने शिवपुर, भुवनेश्वरपुर और बदिकाआश्रम के आसपास के कई गांवों में भी इसी तरह लोगों को ठगा है। रामानुजनगर पुलिस ने प्राथम्यता की शिकायत पर आरोपी रूपेश साहू और ललन साहू के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) धोखाधड़ी और 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

डीजे की आवाज कम करने कहा तो मां-बेटे पर हमला, नाबालिग के पेट में कैची लगाने से हालत गंभीर

गणेश प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान हुआ विवाद, मां के हाथ में भी आई गंभीर चोट; दो आरोपी गिरफ्तार, अन्य की भूमिका की जांच जारी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

गणेश प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट और हमले में बदल गया। खैरवार रोड स्थित घुटरापारा में डीजे की आवाज कम करने की बात कहना एक महिला और उसके नाबालिग बेटे को भारी पड़ गया। आरोप है कि इसी बात को लेकर विवाद के बाद वहां मौजूद महिला-पुरुषों ने मां-बेटे के साथ मारपीट की और धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में नाबालिग के पेट में कैची लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसकी मां के हाथ में भी गंभीर चोट आई है। जानकारी के अनुसार



घुटरापारा में गणेश प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान डीजे काफी तेज आवाज में बजाया जा रहा था। इसी बीच स्थानीय निवासी मंजू गुप्ता और उनकी नाबालिग बेटे ने डीजे की आवाज कम करने के लिए कहा। बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर मौके पर मौजूद

कुछ लोगों ने उनका विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोप-प्रत्यारोप के बीच मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि विवाद के दौरान वहां मौजूद महिला-पुरुषों ने मंजू गुप्ता और उनके बेटे के साथ मारपीट की। इसी दौरान धारदार वस्तु से हमला किए जाने से मंजू गुप्ता

की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने घुटरापारा निवासी गुड्डू गुप्ता,उम्र 35 वर्ष, और उसकी पत्नी पिकी गुप्ता,उम्र 34 वर्ष, को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों से घटना के संबंध में पुछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार घटना में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज,प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह पता लगाया जा रहा है कि विवाद के दौरान कौन-कौन लोग मौके पर मौजूद थे और मारपीट तथा हमले में उनकी क्या भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि जांच में जिन लोगों की सलिमता सामने आएगी,उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बारिश में भी नहीं थमी बप्पा की विदाई,झांकियों के साथ उमड़ा शहर

10 दिन की पूजा के बाद नम आंखों से गणपति को विदा, घड़ी चौक पर सजी झांकियों ने मोहा मन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

दस दिनों तक घरों और पंडालों में पूजा-अर्चना के बाद शुक्रवार को गणपति बप्पा की विदाई हुई। बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। शहर के विभिन्न गणेश पूजा समितियों ने प्रतिमाओं के साथ आकर्षक झांकियां निकालीं। खेल-नागाड़ों की धुन पर नाचते-गाते श्रद्धालु शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए विसर्जन के लिए रवाना हुए। विसर्जन जुलूस के दौरान श्रद्धालुओं ने अबीर-गुलाल उड़कर और जयकारे लगाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। दस दिनों तक साथ रहे विघ्नहर्ता को श्रद्धालुओं ने अगले वर्ष फिर आने की कामना के साथ विदाई दी। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर बाल गंगाधर तिलक गणपति स्थापना



समिति की ओर से घड़ी चौक पर विशेष आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान गणेश की आरती और पूजन से हुई। इसके बाद विभिन्न गणेश पूजा समितियों की ओर से निकाली गई झांकियां घड़ी चौक पहुंचीं। समिति के सदस्यों ने झांकियों का स्वागत किया और भगवान गणेश का पूजन किया। आकर्षक सजावट और धार्मिक विषयों पर आधारित झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहीं।

बारिश के बीच भी दिखा उत्साह : शुक्रवार को रुक-रुककर बारिश होती रही, इसके बावजूद विसर्जन जुलूस में श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही। भक्तों ने नाचते-गाते और जयकारे लगाते हुए गणपति को विदाई दी। श्रद्धालुओं ने परिवार और शहर की सुख-समृद्धि की कामना के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन किया। **जुलूस के दौरान सुरक्षा की कमान पुलिस के हाथ :** विसर्जन जुलूस को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए थे। प्रमुख मार्गों और चौक-चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहा। जुलूस के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने के साथ असाમાजिक तत्वों पर भी नजर रखी गई। एसपी राजेश अग्रवाल, एसपी, सीएसपी सहित पुलिस अधिकारी और जवान व्यवस्था की निगरानी करते रहे।

बृजलाल मानिकपुरी बने मानिकपुरी पनिका समाज के जिलाध्यक्ष

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

भारतीय मानिकपुरी पनिका समाज, जिला सरगुजा का पुनर्गठन किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से बृजलाल मानिकपुरी को जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। उनके मनोनयन पर समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों, सामाजिक प्रतिनिधियों और युवाओं ने खुशी जताते हुए बधाई दी। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष बृजलाल मानिकपुरी ने समाज के शीर्ष नेतृत्व और सामाजिक बंधुओं के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि उन पर जताए गए विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। समाज को संगठित करना, युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जोड़ना तथा सामाजिक कुश्रितियों को दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। बैठक में समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने कहा कि नए नेतृत्व में जिले में सामाजिक एकजुटता और संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। जल्द ही कार्यकारिणी का विस्तार कर नए सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।



एसटी भूमि फर्जीवाड़े में 40 लाख के सौदे का आरोपी गिरफ्तार

- प्रतीक्षा बस स्टैंड के पास 6.25 एकड़ तालाब क्षेत्र की जमीन में हेरफेर का मामला
- फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र और वंशावली के आधार पर बैनामा कराने का आरोप

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।

प्रतीक्षा बस स्टैंड के पास स्थित तालाब क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति की जमीन के फर्जीवाड़े मामले में मणिपुर पुलिस, साइबर सेल और रायपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी आजाद इराकी (43),निवासी मरिजंद मोहल्ला जयनगर, जिला सूरजपुर को रायपुर से पकड़ा है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फर्जी दस्तावेज होने की जानकारी के बावजूद विवादित जमीन का 40 लाख रूप में सौदा किया था। मामले में शामिल अन्य आरोपी फरार हैं,जिनकी तलाश की जा रही है। कलेक्टर कार्यालय सरगुजा की जांच के आधार पर मणिपुर थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस से अनुसार प्रतीक्षा बस स्टैंड के पास खसरा



नंबर 3714 में 0.250 हेक्टेयर (0.231 हेक्टेयर) भूमि स्थित है। यह भूमि नगर निगम के मास्टर प्लान-2021 तथा शासकीय तालाब सूची में दर्ज 6.25 एकड़ तालाब क्षेत्र का हिस्सा है। स्थानीय लोग इसका उपयोग निस्तारी, स्नान और छोट पूजा सहित अन्य सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों के लिए करते रहे हैं। जांच

में सामने आया कि वर्ष 1954-55 से पहले के राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि अनुसूचित जनजाति वर्ग के भू-स्वामी जैलाल पिता बोधन गोड़ के नाम दर्ज थी। आरोप है कि आरोपियों ने मिलीभगत कर फर्जी पूजा प्रमाण पत्र तैयार करवाया। इसके बाद जयलाल पिता देवराम नामक दूसरे व्यक्ति की वंशावली और नामांतरण रिकॉर्ड

का दुरुपयोग कर खुद को जमीन का वारिस बताया गया। पुलिस के अनुसार इसके बाद विक्रेता चंद्रशेखर यादव और अन्य सह-खोतेदारों के साथ मिलकर अनुसूचित जनजाति की भूमि का गैर-अनुसूचित जनजाति के नाम अवैध अंतरण कराया गया और फर्जी बैनामा तैयार किया गया।

दबिश दी और उसे हिरासत में लिया। पुछताछ में पुलिस के अनुसार आरोपी ने फर्जी और कट्टरचित दस्तावेज होने की जानकारी के बावजूद 40 लाख रूपए में विवादित जमीन का सौदा करने की बात स्वीकार की। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस फरार सह-आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले की आगे की जांच जारी है। **कार्रवाई में ये रहे शामिल :** डीएसपी रायपुर क्राइम संजय सिंह, मणिपुर थाना प्रभारी सीपी तिवारी,रायपुर उच्च निरीक्षक गेंदुराम नवरंग,साइबर सेल प्रभारी एएसआई अजीत मिश्रा,एएसआई अनिल पाण्डेय,प्रधान आरक्षक जयदीप सिंह,आरक्षक मनीष सिंह,रमेश राजवाड़े, उमाशंकर साहू,अनिल सिंह तथा रायपुर के आरक्षक संदीप सिंह व महिलाएं सिंह।



नगरपालिका का चुनाव या 2028 की बिसात? बैकुंठपुर में कांग्रेस के एक टिकट पर कई सियासी निशाने

बैकुंठपुर में कांग्रेस का चेहरा कौन? नगरपालिका की कुर्सी के साथ 2028 की बिसात भी...

नगरपालिका की कुर्सी पर किसका चेहरा? कांग्रेस में दावेदार कम, अंदरखाने सियासी हलचल तेज

बैकुंठपुर में कांग्रेस का टिकट किसे? अशोक की दूरी, आशीषों की दावेदारी और अंबिका के नाम पर मंथन...

नगरपालिका चुनाव या विधानसभा की तैयारी? बैकुंठपुर कांग्रेस में चेहरे को लेकर बढ़ा सियासी पैव

कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चेहरा कौन? बैकुंठपुर नगरपालिका से तय हो सकती है अग्रे की सियासी दिशा

अशोक ने बनाई दूरी, आशीषों ने बढ़ाई दावेदारी, अंबिका के नाम पर भी चर्चा... कांग्रेस में कौन बनेगा चेहरा?

बैकुंठपुर नगरपालिका में कांग्रेस का 'चेहरा' तय हो रही है, दावेदारी से ज्यादा रणनीति पर नजर...

इस बार पार्षद नहीं, जनता चुनेगी अध्यक्ष... बैकुंठपुर में कांग्रेस के चेहरे पर सबसे बड़ा सियासी सवाल

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर, 25 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले का नगरीय निकाय चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है, दिलचस्प इसलिए भी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही ऐसे चेहरे पर दावा खेलना चाह रही हैं, जिस पर जनता भरोसा करे और जीत पार्टी की झोली में आ जाए, लेकिन बैकुंठपुर नगरपालिका में कांग्रेस के लिए यह चुनाव सिर्फ अध्यक्ष की कुर्सी तक सीमित नहीं दिखता चुनाव में उम्मीदवारों के चेहरे के बहाने पार्टी के भीतर आगामी विधानसभा चुनाव की बिसात भी बिछती नजर आ रही है। कांग्रेस में दावेदारों की संख्या बढ़ रही है, पिछले चुनाव में कांग्रेस के 11, भाजपा के 7 और दो निर्दलीय पार्षद चुने गए थे, इसके बावजूद अध्यक्ष पद कांग्रेस के हाथ नहीं आया, अध्यक्ष पद के चुनाव में बराबरी की स्थिति बनी और पच्चीस से भाजपा की नवित शिवहरे अध्यक्ष बनीं, लेकिन इस बार ऐसा कोई राजनीतिक गणित नहीं होगा, अब अध्यक्ष किसी पार्षद के वोट से नहीं, सीधे जनता के वोट से बनेगा,

यानी इस बार पार्टी के लिए उम्मीदवार का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है।

अशोक जायसवाल... कांग्रेस के पास मजबूत चेहरा, लेकिन नगरपालिका से दूरी-कांग्रेस के भीतर बैकुंठपुर में जो मजबूत चेहरा माना जाता है, उनमें अशोक जायसवाल का नाम सबसे पहले आता है, आगामी विधान सभा चुनाव में उन्हें विधायक प्रत्याशी के प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है, अशोक जायसवाल नगरपालिका की राजनीति से भी अनजान नहीं हैं, वे स्वयं एक बार नगरपालिका चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरी बार अपनी पत्नी को नगरपालिका चुनाव लड़वा चुके हैं, यानी लगातार दो नगरपालिका चुनावों में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी रही है, इसके बावजूद इस बार उन्होंने नगरपालिका चुनाव से दूरी बना ली है और चुनाव की संशा से इनकार कर दिया है, यही बात कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन रही है, जिस चेहरे को आगामी विधानसभा के लिए मजबूत माना जा रहा है, वही चेहरा नगरपालिका चुनाव से बाहर क्यों है? क्या अशोक जायसवाल सीधे विधानसभा की तैयारी करना चाहते हैं? क्या वे नगरपालिका की राजनीति में लगातार दो बार भागीदारी के बाद अब अगली राजनीतिक पारी विधानसभा के लिए देख रहे हैं? या फिर पार्टी की अंदरूनी रणनीति में नगरपालिका और विधानसभा के चेहरों को अलग-अलग रखा जा रहा है? इन सवालों का जवाब फिलहाल सामने नहीं है, लेकिन उनका चुनाव से पीछे हटना कांग्रेस के लिए अध्यक्ष पद का चेहरा तय करने की चुनौती जरूर बढ़ा रहा है।

अंबिका सिंहदेव... नाम आते ही नगरपालिका से विधानसभा तक पहुंच जाता है सवाल-चौथा और सबसे पेचीदा नाम है पूर्व विधायक अंबिका सिंहदेव का, अंबिका सिंहदेव का, अंबिका सिंहदेव विधायक रह चुकी हैं, उनके पास विधानसभा का अनुभव है और पार्टी ने उन्हें पहले भी विधानसभा चुनाव में मौका दिया है, लेकिन उनके राजनीतिक सफर में एक तरफ 2018 की जीत है तो दूसरी तरफ 2023 का विधानसभा परिणाम भी है, 2023 में भाजपा के भैरालाल राजवाड़े को 66,866 वोट मिले, जबकि अंबिका सिंहदेव को 41,453 वोट मिले, जीत का अंतर 25,413 वोट रहा, यही परिणाम अब उनकी आगामी राजनीतिक भूमिका को लेकर होने वाली चर्चाओं में बार-बार सामने आता है, लेकिन सवाल सिर्फ 2023 की हार का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या अंबिका सिंहदेव के पास अब भी उतना ही स्थानीय जनाधार है, जितना एक मजबूत विधानसभा दावेदार के लिए जरूरी माना जाता है? आपके दिए राजनीतिक आकलन के मुताबिक, उनके सामने अपनी ही पार्टी के लोगों के साथ भरोसे का सवाल और आम जनता के बीच सीधे संपर्क का सवाल भी है, यह वजह है कि कांग्रेस के भीतर यह चर्चा हो सकती है कि आगामी विधानसभा में जनता उन्हें किस रूप में स्वीकार करेगी, यह निष्कर्ष किसी सर्वे के सत्यापित परिणाम के रूप में नहीं, बल्कि स्थानीय राजनीतिक चर्चा और आपके दिए आकलन के रूप में देखा जाना चाहिए।

आशीष यादव उर्फ लाला-दमखम के साथ दावेदारी, लेकिन भरोसा किसका?-

अशोक जायसवाल के बाद कांग्रेस में जो नाम मजबूती से सामने आता है, वह है वर्तमान नगरपालिका उपाध्यक्ष आशीष यादव उर्फ लाला का, आशीष यादव दमखम के साथ अध्यक्ष पद की दावेदारी ठेक रहे हैं, मौजूदा नगरपालिका उपाध्यक्ष होने के कारण उनके पास स्थानीय निकाय की राजनीति का प्रत्यक्ष अनुभव भी है, परिषद की कार्यप्रणाली, वार्डों की राजनीति और शहर की स्थानीय समस्याओं से उनका सीधा जुड़ाव रहा है, इस बार जब अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता करेगी, तो यह अनुभव उनके लिए राजनीतिक आधार बन सकता है, लेकिन कांग्रेस के भीतर असली सवाल यही है कि क्या पार्टी आशीष यादव पर भरोसा करेगी? क्या संगठन उन्हें पूरे शहर का चेहरा मानकर मैदान में उतारेगा? क्या उनके नाम पर कांग्रेस के सभी गुट एक साथ खड़े होंगे? या फिर अध्यक्ष पद के टिकट को लेकर अंदरखाने कोई दूसरा समीकरण तैयार होगा? यही असमंजस फिलहाल कांग्रेस के भीतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव में अध्यक्ष प्रत्याशी को सिर्फ अपने समर्थकों का नहीं, पूरे शहर का चुनाव लड़ना है, इसलिए पार्टी को यह देखा होगा कि जिस व्यक्ति को टिकट दिया जाए, उसके साथ संगठन के साथ-साथ जनता का कितना जुड़ाव है।

आशीष डाबरे-छात्र संघ से शुरू हुई राजनीति, करीब 20 साल का अनुभव-

तीसरा बड़ा नाम आशीष डाबरे का है, आशीष डाबरे राजनीति के पुराने चेहरे हैं, छात्र संघ के समय से राजनीति कर रहे हैं और उनका राजनीतिक अनुभव करीब 20 साल का हो चुका है, राजनीति के साथ संगठन में भी उन्होंने लंबा समय बिताया है, यानी अनुभव के मामले में उनके सामने कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके सामने भी अपनी तरह का राजनीतिक असमंजस है, अंदरखाने की चर्चा यह है कि यदि टिकट के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाया गया और संगठन के भीतर के कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया, तो आगे चलकर नुकसान अपने ही संगठन के लोगों से हो सकता है, राजनीति में यह कोई नई बात नहीं है, टिकट की लड़ाई कई बार चुनाव से पहले ही संगठन के भीतर रिश्तों और समीकरणों को बदल देती है, इसी वजह से आशीष डाबरे ने भी काफी हद तक फैसला पार्टी के ऊपर छोड़ दिया है, पार्टी क्या तय करती है, वही अंतिम होगा, यानी लगभग दो दशक के राजनीतिक अनुभव के बावजूद वे टिकट की लड़ाई को टकराव में बदलने के बजाय संगठन के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं।

अंबिका सिंहदेव के सामने दो रास्ते-विधानसभा या नगरपालिका?

यहीं से नगरपालिका चुनाव कांग्रेस के लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, एक राजनीतिक संभावना यह है कि यदि कांग्रेस अंबिका सिंहदेव को फिर से सक्रिय राजनीतिक भूमिका देना चाहती है तो बैकुंठपुर नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव उनके लिए एक रास्ता बन सकता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अब तक विधानसभा जैसे बड़े चुनाव लड़े हैं, लेकिन स्थानीय निकाय का अनुभव नहीं लड़ा है, नगरपालिका चुनाव उन्हें छोटे और सीधे स्थानीय चुनाव का अनुभव दे सकता है, यह चुनाव वार्ड-वार्ड की राजनीति है, यह घर-घर संपर्क का चुनाव है, यह स्थानीय समस्याओं पर सीधे जवाब देने का चुनाव है, और सबसे महत्वपूर्ण-इस बार अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता करेगी, ऐसे में यदि अंबिका सिंहदेव नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरती हैं और जीतती हैं तो उन्हें शहर की राजनीति में दोबारा सक्रिय होने का अवसर मिल सकता है, इसके बाद वह नगरपालिका के जरिए शहर में अपना जनसंपर्क मजबूत कर सकती हैं और आगे विधानसभा की राजनीति के लिए अपनी जमीन तैयार कर सकती हैं, यही वह राजनीतिक सोच है, जिसकी वजह से कांग्रेस के भीतर अंबिका सिंहदेव को नगरपालिका अध्यक्ष पद का चेहरा बनाने की चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है।

क्या नगरपालिका चुनाव अंबिका सिंहदेव के लिए राजनीतिक पुनर्निर्माण का रास्ता बन सकता है?

यही से नगरपालिका चुनाव कांग्रेस के लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, एक राजनीतिक संभावना यह है कि यदि कांग्रेस अंबिका सिंहदेव को फिर से सक्रिय राजनीतिक भूमिका देना चाहती है तो बैकुंठपुर नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव उनके लिए एक रास्ता बन सकता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने अब तक विधानसभा जैसे बड़े चुनाव लड़े हैं, लेकिन स्थानीय निकाय का अनुभव नहीं लड़ा है, नगरपालिका चुनाव उन्हें छोटे और सीधे स्थानीय चुनाव का अनुभव दे सकता है, यह चुनाव वार्ड-वार्ड की राजनीति है, यह घर-घर संपर्क का चुनाव है, यह स्थानीय समस्याओं पर सीधे जवाब देने का चुनाव है, और सबसे महत्वपूर्ण-इस बार अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता करेगी, ऐसे में यदि अंबिका सिंहदेव नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरती हैं और जीतती हैं तो उन्हें शहर की राजनीति में दोबारा सक्रिय होने का अवसर मिल सकता है, इसके बाद वह नगरपालिका के जरिए शहर में अपना जनसंपर्क मजबूत कर सकती हैं और आगे विधानसभा की राजनीति के लिए अपनी जमीन तैयार कर सकती हैं, यही वह राजनीतिक सोच है, जिसकी वजह से कांग्रेस के भीतर अंबिका सिंहदेव को नगरपालिका अध्यक्ष पद का चेहरा बनाने की चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है।

लेकिन सर्वे ने बदल दिया तो पूरा गणित?

कांग्रेस यदि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में सर्वे को टिकट चयन का महत्वपूर्ण आधार बनाती है तो पुराने चेहरों की राजनीति के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है, शहर मतदाताओं के अनुसार कांग्रेस इस बार सर्वे में सामने आने वाले नामों को अधिक महत्व देने की दिशा में आगे बढ़ रही है, ऐसे स्थिति में सवाल यह होगा कि अंबिका सिंहदेव सर्वे में कहाँ रहती हैं, संभव है कि अंतिम सूची में उनका नाम हो, लेकिन यदि सर्वे को प्राथमिकता दी जाए

अशोक जायसवाल को फिर नगरपालिका में उतारने की चर्चा क्यों?-

अब बात आती है सबसे अलग राजनीतिक संभावना की, यदि कांग्रेस के भीतर अंबिका सिंहदेव के लिए आगामी विधानसभा का रास्ता तैयार करने की रणनीति बनती है तो अशोक जायसवाल की भूमिका पर भी सवाल उठेगा, क्योंकि अशोक जायसवाल को आगामी विधानसभा के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा है, ऐसे में अंदरखाने यह राजनीतिक चर्चा भी हो सकती है कि यदि अशोक जायसवाल को किसी रणनीति के तहत फिर से नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया जाए तो उनकी विधानसभा दावेदारी पर असर पड़ सकता है, यहां दो संभावनाएं बनती हैं, यदि वे नगरपालिका चुनाव जीतते हैं तो उनकी स्थानीय राजनीतिक पकड़ और मजबूत होगी, यदि परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहता तो वही परिणाम उनकी भविष्य की विधानसभा दावेदारी पर राजनीतिक चर्चा का आधार बन सकता है, इसलिए उन्हें नगरपालिका में उतारना या न उतारना भी सिर्फ नगरपालिका का फैसला नहीं होगा।

एक टिकट से कई लोगों का भविष्य तय हो सकता है-

यही बैकुंठपुर नगरपालिका चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू है, यदि आशीष यादव को टिकट मिलता है तो यह स्थानीय निकाय के अनुभव को प्राथमिकता देने का संदेश होगा, यदि आशीष डाबरे को टिकट मिलता है तो संगठन और लंबे राजनीतिक अनुभव को महत्व मिलने की बात कही जाएगी, यदि अंबिका सिंहदेव को टिकट मिलता है तो इसे शहर की राजनीति में उनकी वापसी और भविष्य की राजनीतिक जमीन तैयार करने की रणनीति से जोड़कर देखा जाएगा, और यदि किसी रणनीति के तहत अशोक जायसवाल को मैदान में उतारा जाता है तो इसे उनकी विधानसभा दावेदारी के संदर्भ में भी देखा जाएगा, यानी नाम किसी एक का होगा, लेकिन असर कई नेताओं की राजनीति पर पड़ेगा।

नामों को दो जाती है तो उनकी स्थिति पर सवाल खड़े होंगे, और यही कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा विरोधाभास है, यदि सर्वे को महत्व देना है तो पुराने टिकटों का आधार कितना निर्णायक होगा? अंबिका सिंहदेव को पहले भी दो बार विधानसभा का टिकट मिल चुका है, यदि आगे भी टिकट उसी राजनीतिक परंपरा के आधार पर तय होता है, तो फिर सर्वे में सामने आने वाले नए चेहरों की भूमिका कमजोर हो जाएगी, इसलिए इस बार कांग्रेस के टिकट चयन पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी, सर्वे जीतेगा या पुराना राजनीतिक समीकरण? यह सवाल केवल अंबिका सिंहदेव का नहीं, कांग्रेस के हर संभावित दावेदार का है।

और अगर अंबिका को नगरपालिका में उतार दिया गया तो? - यही वह स्थिति है, जिसमें कांग्रेस एक साथ कई राजनीतिक लक्ष्य साध सकती है, अंबिका सिंहदेव को नगरपालिका अध्यक्ष पद पर उतारना उन्हें शहर में सक्रिय करेगा, उन्हें स्थानीय निकाय का अनुभव देगा, उन्हें जनता के बीच रोजाना काम करने का अवसर देगा, और यदि वह जीतती है तो कांग्रेस के पास शहर में एक अनुभवी राजनीतिक चेहरा होगा, यही कारण है कि अंबिका सिंहदेव का बैकुंठपुर नगरपालिका चुनाव लड़ना कुछ लोगों के लिए आगामी विधानसभा की तुलना में अधिक व्यावहारिक राजनीतिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, यदि वे नगरपालिका चुनाव हारती हैं तो उनकी राजनीतिक स्थिति पर नई चर्चा शुरू होगी, इसलिए यह फैसला जितना बड़ा अवसर है, उतनी ही बड़ी राजनीतिक परीक्षा भी।

पिछली बार पार्षदों का खेल था, इस बार जनता का फैसला- यही इस चुनाव का सबसे बड़ा फर्क है, पिछली बार कांग्रेस के 11 पार्षद जीते थे और भाजपा के 7, इसके बावजूद

अध्यक्ष कांग्रेस का नहीं बन पाया, क्रॉस वोटिंग के बाद मुकाबला बराबरी पर पहुंचा और पच्चीस से भाजपा की नवित शिवहरे अध्यक्ष बनीं, उस समय अध्यक्ष पद के लिए पार्षदों का गणित सबसे महत्वपूर्ण था, इस बार वह गणित नहीं है, इस बार जनता सीधे अध्यक्ष चुनेगी, अब किसी पार्षद को अपने पक्ष में करने से अध्यक्ष नहीं बनेगा, अब किसी पार्षद को नाराजगी से अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं पलटेंगे, अब बराबरी होने पर पच्चीस निकायों का इंतजार नहीं होगा, अब सीधे जनता के वोट गिने जाएंगे, और इसलिए इस बार अध्यक्ष पद का उम्मीदवार ही पूरे शहर में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा होगा।

यही वजह है कि कांग्रेस के सामने टिकट से ज्यादा चेहरे की चुनौती-कांग्रेस को इस बार ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो केवल पार्टी के भीतर स्वीकार्य न हो, बल्कि पूरे शहर में जनता के सामने खड़ा हो सके, उसे अपने वार्ड से बाहर निकलकर पूरे नगरपालिका क्षेत्र में जाना होगा, उसे हर वर्ग से संपर्क करना होगा, उसे अपने पुराने राजनीतिक रिकॉर्ड का जवाब देना होगा, उसे शहर की समस्याओं पर बात करनी होगी, और जनता को यह भरोसा दिलाना होगा कि नगरपालिका की कमान उसके हाथ में सुरक्षित रहेगी, इसलिए इस बार किसी नेता का केवल पार्टी में मजबूत होना पर्याप्त नहीं होगा, उसे जनता में भी मजबूत दिखाई देना होगा, यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर अध्यक्ष पद का चेहरा तय करना इस बार सबसे कठिन फैसला हो सकता है।

अंदरखाने नगरपालिका, निशाने पर विधानसभा- बैकुंठपुर की राजनीति में इस समय सबसे दिलचस्प बात यही है कि सामने नगरपालिका चुनाव है, लेकिन चर्चा विधानसभा की हो रही है, अशोक जायसवाल की विधानसभा दावेदारी की चर्चा है,

अंबिका सिंहदेव की भविष्य की भूमिका पर सवाल है, आशीष यादव नगरपालिका के अनुभव के साथ दावेदारी कर रहे हैं, आशीष डाबरे करीब 20 साल के राजनीतिक अनुभव के साथ संगठन के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, इन सबके बीच कांग्रेस को एक ऐसा चेहरा चुनना है जो सिर्फ चुनाव लड़े नहीं, बल्कि पूरे शहर को अपने पीछे खड़ा कर सके।

अब असली सवाल-कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी? बैकुंठपुर नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस के सामने फिलहाल चार प्रमुख राजनीतिक चेहरे दिखाई दे रहे हैं—

- अशोक जायसवाल-मजबूत स्थानीय चेहरा, आगामी विधानसभा के प्रबल दावेदारों में नाम, लेकिन नगरपालिका चुनाव से दूरी।
- आशीष यादव उर्फ लाला-वर्तमान नगरपालिका उपाध्यक्ष, स्थानीय निकाय का अनुभव और दमखम के साथ दावेदारी।
- आशीष डाबरे — छात्र राजनीति से शुरुआत, करीब 20 साल का राजनीतिक अनुभव और संगठन में लंबी सक्रियता।
- अंबिका सिंहदेव — पूर्व विधायक, विधानसभा का अनुभव, 2023 में 25,413 मतों से हार और अब शहर की राजनीति में दोबारा सक्रिय होने की संभावित राह, चारों के सामने अलग-अलग परिस्थितियां हैं, चारों का राजनीतिक रास्ता अलग है, और चारों के नाम के साथ कांग्रेस की आगे की राजनीति का अलग-अलग गणित जुड़ा हुआ है।

फैसला चाहे जिसका हो, इस बार परीक्षा सीधे जनता की होगी- बैकुंठपुर नगरपालिका में इस बार सबसे बड़ा बदलाव चुनाव प्रक्रिया का है, पिछली बार जनता ने पार्षद चुने थे और पार्षदों के राजनीतिक समीकरण से अध्यक्ष बना था, इस बार जनता पार्षद भी चुनेगी और अध्यक्ष भी सीधे चुनेगी, इसलिए इस बार न सिर्फ राजनीतिक दलों को, बल्कि दावेदारों को भी अपनी रणनीति बदलनी होगी, अब अध्यक्ष का चुनाव बंद कमरे के राजनीतिक समीकरण से नहीं होगा, अब फैसला घर-घर की दस्तक, जनता के भरोसे और सीधे वोट से होगा, और कांग्रेस के लिए यही सबसे बड़ा सवाल है कि वह जनता के सामने कौन सा चेहरा रखती है, क्योंकि इस बार अध्यक्ष पद का उम्मीदवार सिर्फ नगरपालिका अध्यक्ष बनने की लड़ाई नहीं लड़ेगा, वह बैकुंठपुर शहर में कांग्रेस के अगले राजनीतिक अध्याय का चेहरा भी बन सकता है, यही कारण है कि बैकुंठपुर नगरपालिका चुनाव की तारीख और प्रत्याशियों के ऐलान से पहले ही कांग्रेस के भीतर राजनीतिक हलचल तेज है, नगरपालिका की कुर्सी सामने है, लेकिन अंदरखाने विधानसभा की बिसात बिछ रही है, अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस इस बिसात पर किसे आगे करती है, किसे पीछे करती है और किस चेहरे के हाथ में बैकुंठपुर शहर की अगली राजनीतिक कमान देने का फैसला करती है, अंतिम फैसला संगठन करेगा, लेकिन इस बार जीत-हार की मुहर सीधे बैकुंठपुर की जनता लगाएगी।



वंदे मातरम् के सामूहिक स्वर से गूंजा चरचा...राष्ट्रभावना से ओतप्रोत हुआ वातावरण

सरस्वती शिशु मंदिर में 543 भैया-बहनों ने किया सामूहिक गायन,नगर के अन्य विद्यालयों में भी एक ही समय गूंजा राष्ट्रगीत

अतिथियों ने राष्ट्रप्रेम,एकता और जिम्मेदारी का दिया संदेश

**-संवाददाता-
कोरिया/ चरचा,25 सितम्बर 2026
(घटती-घटना)।**

अखिल भारतीय विद्या भारती के निर्देशानुसार सरस्वती शिशु मंदिर, चरचा में 'वंदे मातरम्' सामूहिक गायन कार्यक्रम का गरिमायुय आयोजन किया गया,कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और समाज में राष्ट्रभक्ति,राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रभावना को जागृत एवं सुदृढ़ करना रहा,कार्यक्रम में चरचा नगर के विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य,शिक्षक-शिक्षिकाएं तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,चरचा के प्राचार्य राम लखन यादव उपस्थित रहे,कार्यक्रम के संयोजक एवं सरस्वती शिशु मंदिर के व्यवस्थापक राम सागर सिंह रहे,जबकि अध्यक्षता प्रबंध समिति के अध्यक्ष अंचल किशोर राजवाड़े ने की,विशिष्ट अतिथि के रूप में अजय कुमार सिंह,सहसचिव एवं शासकीय अधिवक्ता तथा प्रदीप कुमार तिवारी,

कार्यकारिणी सदस्य,सरस्वती शिक्षा संस्थान एवं कोरिया विभाग प्रभारी उपस्थित रहे।

543 विद्यार्थियों ने एक साथ किया वंदे मातरम् का गायन-कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सरस्वती शिशु मंदिर चरचा के 543 भैया-बहनों द्वारा एक साथ वंदे मातरम् का सामूहिक गायन रहा, निर्धारित समय पर विद्यालय के विद्यार्थी एक साथ खड़े हुए और एक स्वर में वंदे मातरम् का गायन किया, सामूहिक गायन के दौरान विद्यालय परिसर राष्ट्रभक्ति के भाव से गूंज उठा,इसी क्रम में चरचा नगर के अन्य विद्यालयों में भी एक ही समय पर सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया,हिंद विद्यालय के 410 तथा स्वामी आत्मानंद विद्यालय के 205 विद्यार्थियों ने इसमें सहभागिता की,इसके अलावा आक्सफोर्ड विद्यालय,स्वामी रामदास स्कूल और वैष्णवी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी भी सरस्वती शिशु मंदिर पहुंचकर कार्यक्रम में सहभागी बने।

मुख्य अतिथि राम लखन यादव ने राष्ट्रप्रेम को जीवन में उतारने का किया आह्वान-कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राम लखन यादव ने विद्यार्थियों को राष्ट्र के प्रति सम्मान,अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया,उन्होंने कहा कि राष्ट्रभावना केवल किसी विशेष अवसर पर व्यक्त करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए,बल्कि विद्यार्थियों के दैनिक व्यवहार,शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारियों में भी दिखाई देनी चाहिए,उन्होंने विद्यार्थियों से अपने अध्ययन के प्रति गंभीर रहने,अनुशासन का पालन करने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का आह्वान किया,उनके अनुसार विद्यार्थी देश का भविष्य हैं और उनके भीतर विकसित होने वाली सोच एवं संस्कार आगे चलकर समाज और राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाते हैं।

अजय कुमार सिंह ने एकता और जिम्मेदारी पर दिया जोर-विशिष्ट अतिथि अजय कुमार सिंह ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एकता

और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व से अवगत कराया,उन्होंने कहा कि अलग-अलग विद्यालयों के विद्यार्थियों का एक साथ आकर वंदे मातरम् का गायन करना सामूहिकता और एकता की भावना को प्रदर्शित करता है,उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार, अनुशासन और सामाजिक चेतना को भी अपने जीवन में स्थान देने की बात कही,उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति सम्मान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने से भी प्रकट होता है।

प्रदीप कुमार तिवारी ने विद्यार्थियों को संस्कार और राष्ट्रचेतना से जोड़-विशिष्ट अतिथि प्रदीप कुमार तिवारी ने कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विद्यार्थियों में राष्ट्रभावना और सामाजिक चेतना का विकास शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है,उन्होंने सामूहिक कार्यक्रमों को विद्यार्थियों में एकता, अनुशासन और सहभागिता की भावना विकसित करने वाला माध्यम बताया,उन्होंने कहा कि विद्यालय केवल पाठ्यक्रम की शिक्षा देने का स्थान नहीं,बल्कि

अंचल किशोर राजवाड़े ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बताया आभार

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रबंध समिति के अध्यक्ष अंचल किशोर राजवाड़े ने विभिन्न विद्यालयों से आए प्राचार्यों, शिक्षकों और विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए आयोजन में सहभागिता के लिए आभार व्यक्त किया,उन्होंने कहा कि विभिन्न विद्यालयों की सामूहिक भागीदारी से कार्यक्रम का उद्देश्य और अधिक व्यापक हुआ,कार्यक्रम के संयोजक एवं विद्यालय के व्यवस्थापक राम सागर सिंह ने आयोजन की रूपरेखा और उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए सभी अतिथियों एवं सहभागी विद्यालयों के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया।

एक समय,एक स्वर और एक भाव

कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों की सहभागिता ने इसे सामूहिक स्वरूप प्रदान किया, सरस्वती शिशु मंदिर के 543,हिंद विद्यालय के 410 और स्वामी आत्मानंद विद्यालय के 205 विद्यार्थियों सहित अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों की सहभागिता से चरचा नगर में एक साथ राष्ट्रभावना का संदेश पहुंचा, आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य केवल सामूहिक रूप से 'वंदे मातरम्' का गायन करना नहीं था,बल्कि विद्यार्थियों में राष्ट्रप्रेम,राष्ट्रीय एकता, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना भी था,कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विद्यालयों से आए विद्यार्थी,शिक्षक एवं अतिथि एक साथ मौजूद रहे,सामूहिक गायन के समापन के बाद भी विद्यालय परिसर में उत्साह का वातावरण बना रहा, आयोजन ने विद्यार्थियों को एक साथ आने, एक स्वर में गायन करने और सामूहिक सहभागिता के माध्यम से राष्ट्र के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर दिया।

विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और संस्कार निर्माण का केन्द्र भी है, ऐसे आयोजनों के माध्यम से बच्चों को देश, समाज और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया जा सकता है।

चक्रधर समारोह 2026 में कोरिया के आयुष नामदेव ने मचाई धूम,सुरों से जीता रायगढ़ का दिल

बॉलीवुड सिंगर कविता कृष्णमूर्ति के साथ शानदार समापन,वित्त मंत्री ओपी चौधरी और सांसद देवेन्द्र सिंह ने स्तुति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित



-संवाददाता- कोरिया/बैकुंठपुर,25 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित चक्रधर समारोह 2026 के समापन अवसर पर कोरिया जिले के युवा गायक आयुष नामदेव ने अपनी शानदार गायकी से ऐसी छाप छोड़ी कि रायगढ़ का पूरा पंडाल उनके सुरों से गूंज उठा, समारोह के समापन कार्यक्रम में आयुष ने अपनी आवाज और दमदार मंचीय प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके साथ मशहूर बॉलीवुड गायिका कविता कृष्णमूर्ति की प्रस्तुति ने समारोह के समापन को खास बना दिया। आयुष के मंच पर पहुंचते ही दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया,इसके बाद उन्होंने सूफी, गजल, बॉलीवुड के लोकप्रिय गीतों,पुराने-नए गानों के साथ छत्तीसगढ़ी गीतों की प्रस्तुतियां देकर संगीत की विविधता का रंग बिखेरा,उनकी प्रस्तुति के दौरान दर्शकों में खासा उत्साह नजर आया और पूरा पंडाल उनके गीतों पर झूमता दिखाई दिया।

एक मंच पर संगीत की कई विधाओं का संगम-आयुष नामदेव की प्रस्तुति की खासियत यह रही कि उन्होंने अपनी गायकी में अलग-अलग संगीत विधाओं को शामिल किया,सुफियाना अंदाज से लेकर गजल,बॉलीवुड गीत और छत्तीसगढ़ी गीतों तक उन्होंने अपनी आवाज का अलग रंग प्रस्तुत किया,रायगढ़ में मौजूद संगीत प्रेमियों के लिए यह प्रस्तुति इसलिए भी खास रही कि एक ही मंच पर उन्हें अलग-अलग अंदाज के गीत सुनने का अवसर मिला,आयुष ने अपनी प्रस्तुति के दौरान मंच पर मौजूद दर्शकों से संवाद भी कायम रखा और गीतों के साथ माहौल को लगातार जीवंत बनाए रखा।

मंच पर मिला सम्मान-आयुष नामदेव की प्रस्तुति से प्रभावित होकर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी और धर्मजयगढ़ के सांसद देवेन्द्र सिंह ने उन्हें मंच पर स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, यह सम्मान आयुष के लिए विशेष उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है,

चक्रधर समारोह जैसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक मंच पर प्रस्तुति देने और समारोह के समापन कार्यक्रम में सम्मानित होने से कोरिया जिले के संगीत प्रेमियों और उनके प्रशंसकों में भी उत्साह है।

सोशल मीडिया पर भी छाया आयुष का सुर-समारोह में आयुष की प्रस्तुति का वीर मंच तक ही सीमित नहीं रहा, उनके कार्यक्रम के वीडियो और रीलस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से प्रसारित हो रहे हैं,इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आयुष की प्रस्तुति से जुड़े वीडियो को दर्शकों द्वारा साझा किया जा रहा है,कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं और इन्फ्लुएंसर्स द्वारा भी उनकी प्रस्तुति के वीडियो पोस्ट किए जाने की बात सामने आई है,उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन वीडियो को बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं और आयुष की गायकी की सराहना कर रहे हैं,सोशल मीडिया पर मिल रही प्रतिक्रिया ने आयुष की इस प्रस्तुति को समारोह के मंच से आगे नए दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया है।

कोरिया की प्रतिभा ने प्रदेश के मंच पर बनाई पहचान- चक्रधर समारोह 2026 में आयुष नामदेव की प्रस्तुति को कोरिया जिले की युवा प्रतिभा के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, छोटे शहर और जिले से निकलकर प्रदेश के बड़े सांस्कृतिक मंच पर अपनी पहचान बनाना किसी भी कलाकार के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, आयुष ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से न केवल अलग-अलग संगीत शैलियों को एक साथ प्रस्तुत किया, बल्कि अपनी आवाज और मंचीय आत्मविश्वास से दर्शकों के बीच पहचान भी बनाई, समारोह में मिली सराहना और सम्मान ने उनकी संगीत यात्रा में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया है, चक्रधर समारोह 2026 के मंच से निकली आयुष नामदेव की आवाज अब सोशल मीडिया के जरिए भी नए श्रोताओं तक पहुंच रही है, कोरिया से रायगढ़ तक उनकी इस प्रस्तुति ने युवा कलाकारों की प्रतिभा और संभावनाओं को एक बार फिर सामने ला दिया है।

पांडवपारा खदान में फर्जी B T C के सहारे मजदूरों को रिप्लेसर के रूप में काम कराने का आरोप

शिकायत में 20 से 25 हजार रुपये लेकर फर्जी बीटीसी तैयार कराने का दावा

12 दिन के बीटीसी पर काम कराने और 48 दिन के अनुभव की शर्त दरकिनार करने का आरोप,निष्पक्ष जांच की मांग

**-संवाददाता-
पटना/पांडवपारा,25 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।**

झिलमिली सह क्षेत्र के पांडवपारा खदान में मजदूरों से जुड़े दस्तावेजों और रिप्लेसर के रूप में काम कराने की व्यवस्था को लेकर गंभीर शिकायत सामने आई है, 25 सितंबर 2026 को की गई लिखित शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ मजदूरों को कथित तौर पर केवल 12 दिन के बीटीसी के आधार पर रिप्लेसर के रूप में काम में लगाया जा रहा है, जबकि संबंधित कार्य के लिए 48 दिन के रिकॉर्ड/अनुभव की आवश्यकता बताई गई है, शिकायतकर्ताओं ने आरोपों की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में संबंधित सब एरिया प्रबंधन को संबोधित करते हुए कहा गया है कि पांडवपारा कोलरी खदान में कार्यरत मजदूरों की जानकारी के अनुसार कुछ लोगों को कम अवधि के बीटीसी के आधार पर रिप्लेसर के रूप में काम में लगाया जा रहा है, शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों द्वारा पैसे लेकर कथित तौर पर फर्जी बीटीसी तैयार कराए जाने और उसके आधार पर काम दिलाते जाने की व्यवस्था चल रही है।

12 दिन के बीटीसी पर रिप्लेसर बनाने का आरोप

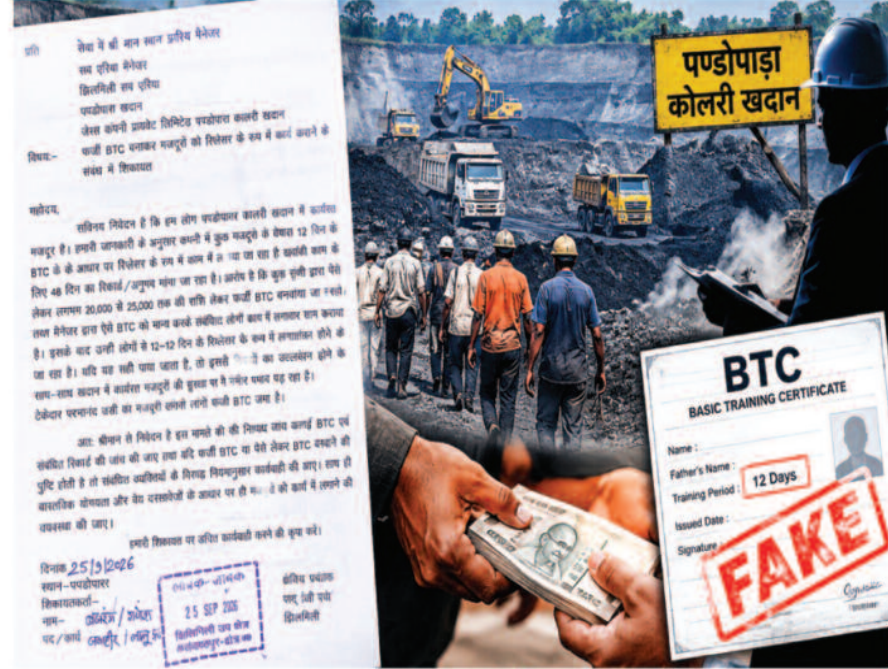
शिकायत में कहा गया है कि कुछ मजदूरों को केवल 12 दिन के बीटीसी के आधार पर रिप्लेसर के रूप में काम कराया जा रहा है, जबकि काम के लिए 48 दिन का रिकॉर्ड अथवा अनुभव मांगा जाता है,शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि यदि यह व्यवस्था सही पाई जाती है तो इससे निर्धारित प्रक्रिया और पात्रता संबंधी नियमों के पालन पर सवाल खड़े होते हैं, शिकायत में इस बात की भी जांच की मांग की गई है कि जिन मजदूरों को रिप्लेसर के रूप में काम में लगाया गया है, उनके बीटीसी दस्तावेज वास्तविक हैं या नहीं और उनमें दर्ज प्रशिक्षण अथवा कार्य दिवसों का रिकॉर्ड किस आधार पर तैयार किया गया।

20 से 25 हजार रुपये लेकर फर्जी बीटीसी बनाने का दावा

शिकायत का सबसे गंभीर हिस्सा कथित रूप से 20 हजार से 25 हजार रुपये लिए जाने से जुड़ा है, शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों से पैसे लेकर फर्जी बीटीसी तैयार कराया जा रहा है और बाद में ऐसे दस्तावेजों को मान्य मानकर संबंधित व्यक्तियों को काम में लगाया जा रहा है, हालांकि,यह आरोप फिलहाल शिकायत में लगाए गए दावों तक सीमित है,दस्तावेज में किसी कथित लेनदेन की स्वतंत्र पुष्टि अथवा जांच रिपोर्ट का उल्लेख नहीं है, इसलिए वास्तविक स्थिति सामने लाने के लिए बीटीसी जारी करने वाले रिकॉर्ड,प्रशिक्षण अवधि,भुगतान संबंधी दस्तावेज और रिप्लेसर ड्यूटी से जुड़े अभिलेखों की जांच आवश्यक होगी।

एक ही व्यक्ति से 12-12 दिन काम कराने का आरोप

शिकायत में यह भी कहा गया है कि कथित रूप से ऐसे बीटीसी के आधार पर लोगों को 12-12 दिन के रिप्लेसर के रूप में लगातार काम कराया जा रहा है,यदि यह व्यवस्था वास्तव में संचालित हो रही है तो यह भी जांच का विषय होगा कि प्रत्येक मजदूर की पात्रता का सत्यापन किस स्तर पर किया गया और ड्यूटी लगाने से पहले उसके दस्तावेजों की जांच किस अधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति ने की,शिकायतकर्ताओं ने आशंका जताई है कि यदि फर्जी अथवा अपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर खदान में मजदूरों को कार्य कराया जा रहा है तो इसका असर केवल नियमों के पालन तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि खदान में कार्यरत मजदूरों की सुरक्षा से भी जुड़ा गंभीर विषय बन सकता है।



ठेकेदार की भूमिका की भी जांच की मांग...

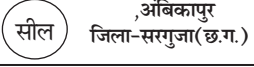
शिकायत में ठेकेदार की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं,शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि यह जांच की जाए कि संबंधित मजदूरों के बीटीसी किस माध्यम से तैयार हुए,उन्हें काम में किसने लगाया और ठेकेदार स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन किस प्रकार किया गया, इसके लिए केवल मौखिक जांच के बजाय संबंधित मजदूरों के बीटीसी,प्रशिक्षण रिकॉर्ड, उपस्थिति पंजी,रिप्लेसर ड्यूटी रिकॉर्ड,भुगतान विवरण और ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का मिलान किया जाना जरूरी होगा।

निष्पक्ष जांच और वैध दस्तावेजों के आधार पर काम देने की मांग...

शिकायतकर्ताओं ने संबंधित प्रबंधन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है,शिकायत में कहा गया है कि बीटीसी एवं उससे संबंधित रिकॉर्ड की जांच की जाए और यदि फर्जी बीटीसी अथवा पैसे लेकर दस्तावेज तैयार कराने की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए, साथ ही यह मांग भी की गई है कि मजदूरों को वास्तविक योग्यता और वैध दस्तावेजों के आधार पर ही काम में लगाया जाए, ताकि पात्र मजदूरों के अधिकार प्रभावित न हों और खदान में सुरक्षा मानकों के साथ किसी तरह का समझौता न हो।

अब रिकॉर्ड की जांच से खुलेगा मामला

पांडवपारा खदान से सामने आई शिकायत में लगाए गए आरोपों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए किसी व्यक्ति या अधिकारी को दोषी मानने से पहले दस्तावेजों की जांच आवश्यक है,यदि बीटीसी के रिकॉर्ड,प्रशिक्षण अवधि,रिप्लेसर ड्यूटी और भुगतान से संबंधित अभिलेखों में शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है,तो मामला गंभीर हो सकता है,अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 12 दिन के बीटीसी पर कितने लोगों का रिप्लेसर बनाया गया,48 दिन के अनुभव की शर्त वास्तव में क्या है, बीटीसी किस प्रक्रिया से जारी हुए और कथित 20-25 हजार रुपये के लेनदेन का कोई रिकॉर्ड है या नहीं? इन सवालों का जवाब खदान प्रबंधन द्वारा कराई जाने वाली निष्पक्ष जांच और संबंधित दस्तावेजों के परीक्षण से ही सामने आ सकेगा।





CMYK